

प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2014 प्र0सु0रि0स0 01
दिनांक 16.1.2014
2. धारा 409,420 आई.पी.सी.8 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988
3. (क) अपराध की घटना : 2005-2006 से 2007-2008
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 16.1.2014 समय 12.30 पी0एम0.
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 05
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थल: (क) पंचकुला
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता
नाम नि0 सुरेश कुमार 191 एच.ए.पी
पिता का नाम
राष्ट्रीयता भारतीय
व्यवसाय सरकारी नौकरी
पता थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकुला
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
डा0 वी.पी. सिंह राणा वासी गांव घामडोज थाना भौंडसी जिला गुड़गांव
लिंग पुरुष
भाषा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :- सेवा मे एस.एच.ओ. साहब जी, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला सैक्टर-17, पंचकुला, निवेदन है कि जांच क्रमांक 2 दिनांक 20.04.2012 पंचकूला, विरुद्ध श्री के0 एल0 मन्हास, भा0व0से0, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा वन विभाग, पंचकूला, के विरुद्ध दर्ज

रजिस्टर होकर कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 42/10/12-3 चौ0 (1) दिनांक 11.04.2012 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर होकर पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें डा0 वी0पी0 सिंह राणा वासी गांव घामडोज जिला गुडगांव व अन्य की शिकायत के आधार पर दर्ज रजिस्टर हुई थी जिसमें आरोप था कि श्री एल0के0 मिन्हास, आई0एफ0एस0, पी0सी0सी0एफ0-कम-एम0डी0, एच0एफ0डी0सी0 लि0 पंचकूला द्वारा जब वह सदस्य सचिव, स्टेट मैडिसन प्लांट बोर्ड, वन विभाग सैक्टर-6, पंचकूला में कार्यरत थे तो औषधियों की खेती करने वाले कृषकों से कुल लागत की सबसिडी का 10 प्रतिशत हिस्सा रिश्वत लेकर दुसरी किस्त जारी करवाना । जिसकी पड़ताल श्री मनवीर सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला द्वारा की गई थी जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया है कि वर्ष 2002 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, आयूश विभाग भारत सरकार द्वारा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड का गठन किया। इसी नीति अनुसार इस परियोजना राशि की कुल लागत का 30 प्रतिशत अनुदान होता है, जिसमें से पहली किस्त अनुदान के रूप में 30 प्रतिशत का आधा दिया जाता है। प्रथम किस्त अनुदान राशि के प्रयोग के बाद सम्बन्धित किसान को राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, उसके बाद राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड परियोजना ठीक पाये जाने पर दुसरी किस्त की राशि जारी करके राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड को भेजता है। बोर्ड द्वारा सम्बन्धित किसान को यह राशि ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित बैंक को भेज दी जाती है। वर्ष 2005 में महात्मा गांधी मार्केट, कैथल में एग्री क्लीनिक क्रोप केयर सैन्टर कन्सलटैन्ट के नाम से दुकान खोलकर किसानों को औषधीय खेती करने की जानकारी देना, किसानों को औषधीय पौधें व बीज उपलब्ध करवाना, किसानों से उनकी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने व सलाह देने के बदलें पांच से दस हजार रुपये तक की फीस लेना पाया गया है। जो एग्री क्लीनिक व एग्री बिजनेस डिप्लोमा न होने के कारण किसानों को औषधि खेती बारें सलाह देने के लियें सक्षम नहीं था। श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0सें0 को दिनांक 29.08.2007 को राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2005-06 में कुल 85 परियोजनाओं की मन्जूरी उपरान्त राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा सबसिडी (अनुदान) की पहली किस्त 160.68 लाख रुपये राशि सीधे ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित किसानों को दी गई। 26 किसानों को वर्ष 2010 में सबसिडी (अनुदान) की दूसरी किस्त 50.96 लाख रुपये राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड पंचकूला द्वारा राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त होने उपरान्त जारी की जानी पाई गई। वर्ष 2006-07 में कुल 75 परियोजनाओं की पहली किस्त 137.449 लाख रुपये राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त होने पर राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड द्वारा सबसिडी (अनुदान) की राशि ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित किसानों को तथा वर्ष 2006-07 में कुल 75 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाओं की दूसरी किस्त की राशि 5.48 लाख रुपये

राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त होने पर राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड, पंचकूला द्वारा सम्बन्धित किसानों को जारी की गई है। वर्ष 2007-08 में कुल 38 परियोजनाओं की मन्जूरी उपरान्त सबसिडी की राशि राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त होने उपरान्त राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड, पंचकूला द्वारा 35 किसानों को सबसिडी की पहली किस्त 43.67 लाख रुपये ड्राफ्ट द्वारा जारी की जानी तथा तीन किसानों के कागजात पूरे न होने के कारण प्रथम किस्त जारी नहीं की गई जिन-2 किसानों को दुसरी किस्त की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई, उन किसानों की दुसरी किस्त की मन्जूरी के लिये सभी औपचारिकतायें पूर्ण करके राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, दिल्ली को लिखा। स्वीकृति उपरान्त दुसरी किस्त की अनुदान राशि प्राप्त हुई, वह सम्बन्धित किसानों को जारी की जानी नहीं पाई गई है। बोर्ड द्वारा सम्बन्धित किसानों को वर्ष 2005-06 व 2006-07 में ली गई अनुदान राशि के उपयोकिगता प्रमाण पत्र भेजने बारे बार-2 पत्र लिखे जाने पाये गये है। किसानों द्वारा उपयोकिगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण दुसरी किस्त की राशि उनको जारी नहीं करनी पाई गई है। डा० वी०पी० सिंह राणा की गतिविधियां सदिग्ध पाई जाने पर श्री के०एल० मन्हास, भा०व०से०, सदस्य सचिव, राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड, हरियाणा द्वारा नैशनल मैडिसनल प्लांट बोर्ड, दिल्ली को पत्र लिखते हुये प्रार्थना की थी, कि वह अपने स्तर पर परियाजनाओं के क्रियान्वय (लागू करना) की जांच कराये। जिस पर नैशनल मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली ने सरकारी हित में हरियाणा में अनुबन्धित कृषि परियोजना के मुल्यांकन हेतु एग्रीकल्चरल फाईनेंस कार्पोरेशन ने कैथल और करनाल के किसानों की अनुबन्धित कृषि परियोजना की मानिटिरिंग सम्बन्धित रिपोर्ट राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली को भेजी। जिस पर राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली ने राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड, को दिनांक 02.07.2008 को निर्देश दिये, कि डा० वी०पी० सिंह राणा की गतिविधियों की जांच करवा कर इसकी छानबीन करें। जिसकी बोर्ड द्वारा जांच करवाने उपरान्त दिनांक 21.08.2009 व दिनांक 23.08.2009 को स्थानीय अखबारों में डा० वी०पी० राणा के विरुद्ध सलाह जारी करवा दी। जिस पर डा० वी०पी० राणा ने श्री के०एल० मन्हास, भा०व०से० के प्रति रंजिश रखते हुये जिला करनाल के तीन किसानों श्री राजेश कुमार, बलवान सिंह वासीगण चोचड़ा जिला करनाल व श्री अशोक कुमार वासी गांव सालवन जिला करनाल को यह आश्वासन दिया कि वह उन्हें उनकी सबसिडी की दुसरी किस्त दिलवायेगा, जिसके लिये उन तीनों को अपने-अपने शपथ पत्र देने होंगे। दिनांक 21.05.2010 को डा० वी०पी० सिंह राणा ने उक्त तीनों किसानों को करनाल अदालत में बुलाकर उनसे श्री के०एल० मन्हास, भा०व०से० को उनकी सबसिडी की दूसरी किस्त जारी करवाने के बदले सबसिडी राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा बतौर रिश्वत दिनांक 12.03.2009 को उनके कार्यालय वन भवन, सैक्टर-6, पंचकूला में देने बारे शपथ पत्र तैयार करवाये और यह शपथ पत्र श्री परवेज अहमद, भा०व०से० को शिकायत के रूप में दिलवाये जाने पाये गये है। डा० वी०पी० सिंह राणा शिकायतकर्ता द्वारा सर्व श्री जसबीर सिंह, सुरेन्द सिंह,

सतीश कुमार, अनिल, रणजीत, बलदेव, जसवन्त, मुकेश कुमार, फुल सिंह, कुलदीप सिंह, रामपाल, विक्रम, राजेश, मुनिश कुमार, हुक्त चन्द, रणबीर, रघुबीर, रामदयाल व राजेश कुमार, बलवान व अशोक कुमार शिकायतकर्ता निवासीगण जिला कैथल, करनाल व भिवानी से कुल 14,61,800/- रुपये की राशि किसानों से बहला-फुसला कर धोखाधड़ी से उनकी सबसिडी की दूसरी किस्त जारी करवाने के बदले श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0से0 के नाम से ली जानी पाई गई है। डा0 वी0पी0 सिंह राणा ने अपने कथन मे भी माना है कि उसने किसानों से श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0से0 को देने के लिये सबसिडी की दूसरी किस्त की राशि का 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में किसानों से प्राप्त किया है, परन्तु डा0 वी0पी0 सिंह राणा ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवा सका जिससे यह साबित हो सके, कि किसानों से जो राशि कमीशन के रूप में डा0 वी0पी0 सिंह राणा ने प्राप्त की, वह उसने श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0से0 को दी हों। बलवान सिंह, राजेश कुमार व अशोक कुमार शिकायतकर्ताओं ने भी अपने-अपने कथन मे माना है, कि डा0 वी0पी0 सिंह राणा ने उनसे सबसिडी की दूसरी किस्त जारी करवाने के बदले, श्री के0एल0 मन्हास भा0व0से0 के नाम से 10 प्रतिशत की राशि कमीशन के रूप मे ली है। यह भी बताया कि उन्होंने श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0से0 को कोई राशि सबसिडी की दूसरी किस्त जारी करवाने के बदले बतौर रिश्वत नहीं दी है, बल्कि यह राशि उनसे डा0 वी0पी0 सिंह राणा ने ली थी। अतः जांच पर पाया गया कि विभागीय अधिकारियों की आपसी रंजिश के कारण डा0 वी0पी0 राणा ने तीनों शिकायतकर्ताओ को माध्यम बनाकर श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0से0 को रिश्वत देने का आरोप लगाकर, ये शपथ पत्र देने प्राप्त किये जाने पाये गये है। श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0से0 के विरुद्ध लगाये गये आरोप में कोई सच्चाई सामने नहीं आई है, बल्कि डा0 वी0पी0 सिंह राणा द्वारा किसानों को बहला-फुसला कर व धोखाधड़ी से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, औषधीय पौधों के बीज मंहगी दरों पर उपलब्ध करवाने व विभाग के अधिकारियों के नाम से किसानों को उनकी सबसिडी की दूसरी किस्त जारी करवाने के बदले कुल 14,61,800/- रुपये की राशि रिश्वत के रूप में लेनी पाई गई है। डा0 वी0पी0 सिंह राणा के विरुद्ध मुकदमा धारा 409, 420, भा0दं0सं0 व 8 भ्रष्टाचार अधिनियम के अर्न्तगत अंकित करवाये जाने का सुझाव दिया जाना पाया गया है। इस लिए डा0 वी0पी0 सिंह राणा पुत्र श्री भोज राज गांव घामडोज, थाना भौंडसी, जिला गुडगांव के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अंकित करवाये जाने का सुझाव निदेशक रा0चौ0ब्यूरो पंचकूला के पत्र क्रमांक 25537/रा0चौ0ब्यूरो(ह) पंचकूला दिनांक 30.10.13 के अनुसार अन्तिम रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग चण्डीगढ़ को भेजी गई थी। जिसका परिक्षण करने उपरान्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 42/10/12-3 चौ0 (1) दिनांक 17.12.13 के अनुसार डा0 श्री वी0पी0 सिंह राणा वासी गांव घामडोज थाना भौंडसी जिला गुडगांव के विरुद्ध 409, 420 आई.पी.सी. व धारा 8 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने के आदेश प्राप्त हुए है अतः श्री

डा० वी०पी० सिंह राणा पुत्र श्री भोज राज गांव घामडोज, थाना भौंडसी, जिला गुड़गांव के विरुद्ध धारा 409, 420, भा०दं०सं० व 8 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करने के लिए तहरीर दी जा रही है । मुकदमा दर्ज करके तहरीर कायमी मुकदमा आईन्दा तफतीश मौखिक आदेश अफसरान बाला पुलिस अधीक्षक रा०चौ०ब्यूरो,ह० पंचकूला मन निरीक्षक के हवाले की जाये व अभियोग अकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्वच्छ प्रतियां ईलाका मैजीस्ट्रेट व अफसरान बालान की सेवा मे भिजवाई जाये । अज थाना हस्त-नि० सुरेश कुमार 191 एच.ए.पी थाना रा०चौ०ब्यूरो, पंचकूला अज थाना हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा हजा वाजुर्म अनुसार दर्ज रजिस्टर किया जा कर कार्बन कापीयां तैयार की गई जो बजरिया डाक अफसरान बाला व इलाका मैजीस्ट्रेट की सेवा मे भेजी जा रही है मन निरीक्षक ने नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर रखी गई जिसका आईन्दा अध्ययन करके तफतीश अमल मे लाई जावेगी ।

हस्ता / -
नि० सुरेश कुमार 191 एच.ए.पी
थाना रा०चौ०ब्यूरो, पंचकूला ।